उसके क्या कारण हैं और उसकी लागत में कितनी वृद्धि होगी तथा कितनी समय अधिक लगेगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) जोधपुर रेलवे कम्पलेक्स में प्रधान डाक घर भवन के निर्माण के लिए समय सीमा प्रारंभ में बीस माह निर्धारित की गई थी।

(ख) और (ग) जी नहीं। निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण अनुबंध (संलग्न) में दिए गए हैं। इस अवधि के लगभग एक वर्ष तक बढ़ जाने की संभावना है। इससे आने वाली फालतू लागत, भवन सामग्री के संचालन मूल्यों में वृद्धि और ठेके की मौजूदा नियम और शर्तों के अनुसार श्रमिकों के न्यूनतम पारिश्रमिक में वैधानिक/न्यायसंगत बढ़ोत्तरी तक सीमित होगी।

अनुबंध

(1) डाक विभाग और रेलवे विभाग के हित में स्थान का परिवर्तन;

(2) क्षेत्र में सूखे की स्थिति के कारण पानी की कमी;

(3) लेवी सीमेंट का उपलब्ध न होना; और

(4) फसल के दौरान और दीपावली त्यौहार के अवसर पर श्रमिक उपलब्ध न होना।

बरईपुर, उत्तर प्रदेश मे पोस्टमैन की नियुक्ति

1979. **श्री शंकर सिंह वाघेला:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के ग्राम बरईपुर के एक दिहाड़ी वाले पोस्टमैन से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उसने उसी पोस्ट आफिस में अपनी सेवाओं को नियमित किये जाने के बारे में लिखा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिहाड़ी पर कार्यरत उक्त पोस्टमैन के वैध दावे को अनदेखा करते हुए उस पोस्ट आफिस में एक ऊंची जाति के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Interim relief to the IDPL Supervisors

1980. SHRI JERLIE E. TARIANG: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1381 given in the Rajya Sabha on the 9th May, 1988 and state:

(a)whether interim relief has since been paid to the Supervisors of the Indian Drugs & Pharmaceuticals Limited with effect from the 1st January, 1986; and

(b) if not, by when it is likely to be paid?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGALRAO): (a) and (b) The pay scales of Supervisors of Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited have been revised effective from 1-10-1985 for a period of 4 years and as such they are not entitled to interim relief as per the BPE guidelines.

International Finance Corporation Assistance for private sector power projects

1981. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the International Finance Corporation has decided to finance the private sector power projects in the country;

(b) if so, whether the four existing private sector power companies in the country are in touch with the I.F.C. for financing their expansion projects; and

(c) if so, to what extent power projects in private sector will be established, to what extent these funds have been provided to them and to what extent this decision will help in improving the power position in the country?